

प्रति

पी०के० महान्ति  
सचिव  
उत्तराखण्ड शासन

संदर्भ में

गिरेशक,  
पंचायतीराज  
उत्तराखण्ड, देहरादून

पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग देहरादून दिनांक २५ जुलाई, 2007

विषय— वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु विभिन्न वर्षनबद्ध मर्दों में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 189/XII/2007/82(32)/2003, दिनांक 30 मार्च, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अन्तर्गत पंचायतीराज निदेशालय अधिकारान हेतु कुल रु 23,96,000.00 (रु ३६८५ लाख छियानब्दे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित वर्षनबद्ध मानक मर्दों में व्यय हेतु आपके निवारन पर रखाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष र्योकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रु० में)

क्र. सं.	मानक मर्द	वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक में वर्जट प्राविधान	शासनादेश संख्या 189 दिनांक 30.03.07 के द्वारा अवमुक्त धनराशि	(धनराशि हजार रु० में)
1.	०१-पैठन	1350	484	866
2.	०३-महगाइ भल्ला	810	254	556
3.	०४-यात्रा व्यय	20	18	2
4.	०६-अन्य भल्ले	149	59	90
5.	०८-कार्यालय व्यय	100	37	63
6.	०९-विद्युत देय	18	18	0
7.	१०-जलकर/जल प्रभार	9	9	0
8.	१३-ठलौफोन व्यय	110	37	73
9.	१५-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पैटोल भाड़ी की खरीद	300	83	217
10.	१७-किराया उपशूलक और कर स्वामित्य	144	48	96
11.	४८-महगाइ वलन	675	242	433
	योग	3685	1289	2396

(रु० तेईस लाख छियानब्दे हजार मात्र)

२. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवतान नहीं किया जायगा तथा सम्बन्धित अधिकारान हत् आपकरकानुसार फान्ट अपने सार से किया जाय।

३. उक्त आवृत्ति धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आपकरकानुसार मासिक व्यय की सारणी बनाकर ही किया जाय।

४. इस कदल धालू कार्यों के लिए ही व्यय किया जायगा।

५. उक्त आवृत्ति धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/ जारी होने पाले मितव्यवता रान्वन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवृत्ति धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय।

6. निर्माण कार्य एवं सामग्री कय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक / प्राविधिक स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर जौ जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय ।

7. उक्त आविटा धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपञ्ची-०१०५०-१३ पर प्रत्येक माह की ७ वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-१९ के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-२५१५-अन्य ग्राम्य पिकास कार्यक्रम-आयोजनतर-००१-निदेशन तथा प्रशासन-०४ पंचायतीराज निदेशालय अधिकारी की सुसंगत प्राधिकारी इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ५९९ / XXVII(I)/2006, दिनांक १२ जुलाई, २००७ के द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

( पी०क० महान्ति )

सचिव ।

संख्या ४३८ / XII/०७/८२(३२)/२००३ तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून ।
२. परिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
३. जिलाधिकारी, देहरादून ।
४. निदेशक, कोपागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड २३ लक्षी रोड देहरादून ।
५. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून ।
६. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के आवलोकनार्थ ।
७. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-४ उत्तराखण्ड शासन ।
८. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशासन सचिवालय देहरादून ।
९. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

१५ अगस्त २०१५

(जे०पी० जोशी )

उप सचिव ।